

OPEC+ उत्पादन रणनीति में बदलाव

प्रलिस के लयि:

पेट्रोलयिम नरियातक देशों का संगठन, K-शेपड रकिवरी, अंतरराषट्रीय ऊरजा एजेंसी (IEA), वशिव वयापार संगठन (WTO)

मेन्स के लयि:

वैश्वकि तेल आपूरतगितशीलता और OPEC+, भारत की ऊरजा सुरक्षा और तेल आयात पर नरिभरता

[स्रोत: द हट्टि](#)

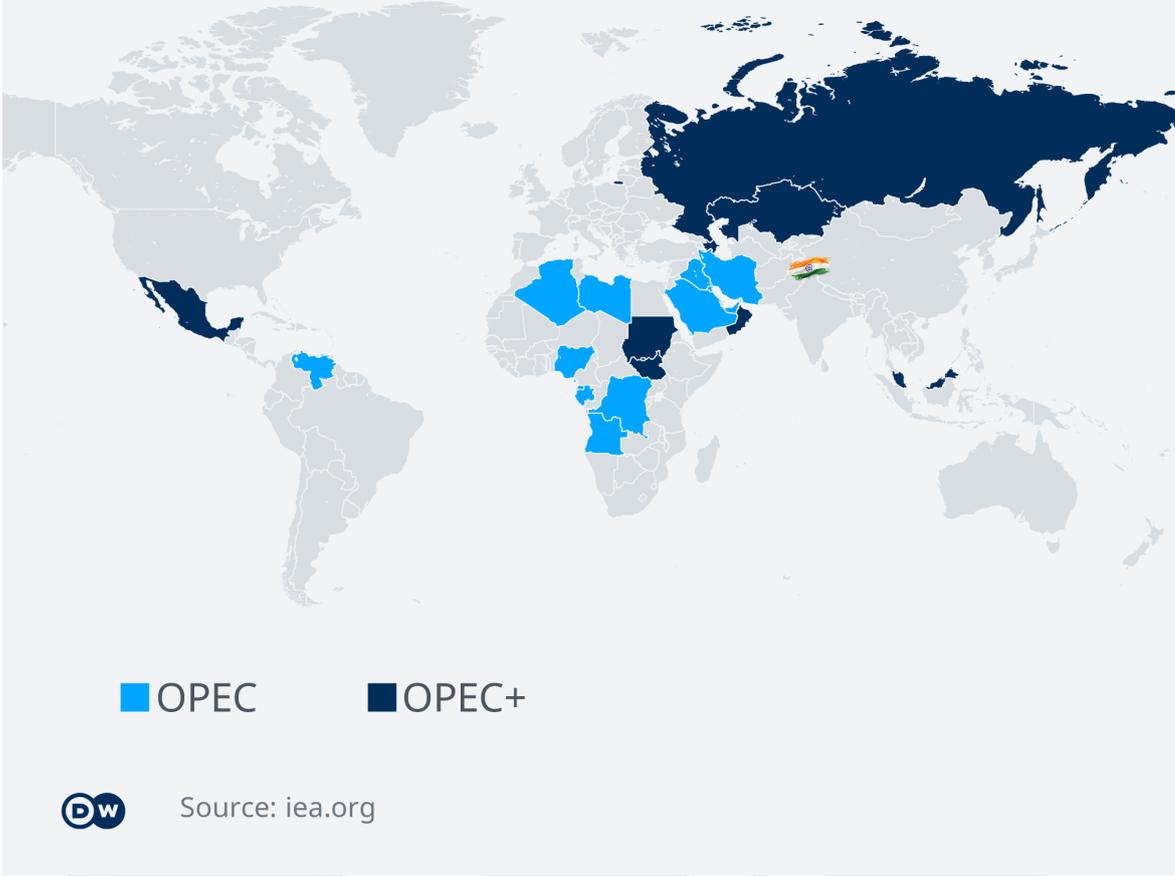
चरचा में क्यो?

सऊदी अरब के नेतृत्व वाले पेट्रोलयिम नरियातक देशों के संगठन (OPEC)+ समूह ने तेल उत्पादन में 411,000 बैरल प्रतदिनि (BPD) की वृद्धिकरने का नरिणय लया है। यह उत्पादन वृद्धि का लगातार तीसरा महीना है, जो वर्ष 2023 में शुरू की गई स्वैच्छकि उत्पादन कटौती को धीरे-धीरे परविरतति कर रहा है।

पेट्रोलयिम नरियातक देशों का संगठन

- OPEC एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है।
 - OPEC में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला शामिल हैं।
 - OPEC सदस्य देशों के बीच तेल नीतियों का समन्वय करने के लिये कार्य करता है ताकि स्थिर कीमतें, उपभोक्ताओं को नरितर आपूरतगि और नविशकों के लिये उचित रटिरन सुनश्चिति कया जा सके।
 - OPEC देश वशिव के लगभग 30% कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं, 80% प्रमाणति भंडार उनके पास हैं और वैश्वकि नरियात में इनका योगदान लगभग 50% है तथा सऊदी अरब OPEC में सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- OPEC+ का गठन वर्ष 2016 में OPEC और 10 अन्य तेल उत्पादक देशों के बीच गठबंधन के रूप में कया गया था, जिसका उद्देश्य अमेरिकी शेल तेल के उत्पादन में वृद्धिके कारण तेल की कीमतों में हुई गरिवट के दृषटगित प्रतसिपर्द्धा करना था।
 - OPEC+ में OPEC के सदस्यों के अतरिकित अजरबैजान, बहरीन, बरुनेई, कज़ाखस्तान, मलेशया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षणि सूडान और सूडान शामिल हैं।
 - OPEC और OPEC+ देश संयुक्त रूप से वैश्वकि तेल उत्पादन का लगभग 60% उत्पादन करते हैं।

OPEC+ members in 2022

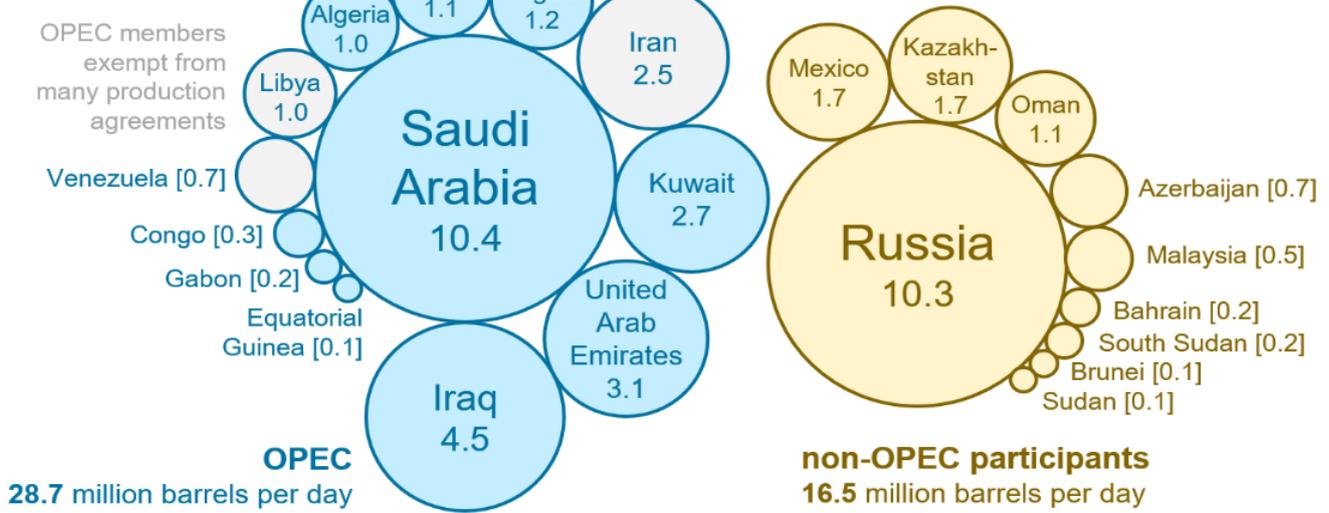


OPEC+ द्वारा तेल उत्पादन में वृद्धि के कारण क्या थे?

- उत्पादन में कटौती का अपर्याप्त प्रभाव: वर्ष 2023 में, आठ OPEC+ सदस्यों ने तेल की गरिती कीमतों के दृष्टिगत स्वेच्छा से तेल उत्पादन में प्रतिदिन 2.2 मिलियन बैरल (bpd) की कटौती करने का नरिणय लया।
 - इन कटौतियों के बावजूद, तेल की वैश्विक कीमतों में गरिावट जारी रही, जो बाज़ार पर अपर्याप्त प्रभाव का संकेत है।
- OPEC+ के अंतर्गत अतउत्पादन में वृद्धि: कज़ाखस्तान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और नाइजीरया जैसे देशों ने अपनी नरिधारति सीमाओं से अधिक तेल का उत्पादन कया। इस वषिय में सऊदी अरब चतिति था चूकउसने लगभग 3 मिलियन bpd की सबसे अधिक कटौती की थी।
- कोवडि के बाद बाज़ार की कमज़ोरी: महामारी के बाद आर्थिक पुनर्र्प्राप्ति **K-आकार** की रही है, जिसके परिणामस्वरूप तेल की मांग में कमज़ोरी और असमानता देखी गई है। तेल बाज़ार में अब OPEC+ के बाहर कई स्वतंत्र उत्पादक हैं, जिससे यह और अधिक जटिल हो गया है।
 - महंगे अपतटीय और कठनि कषेत्रों में अत्यधिक नविश कया गया है, जहाँ राजनीतिक तथा आर्थिक कारणों से, भले ही लाभ कम हो, उत्पादन जारी रखना आवश्यक है।
 - रूस, ईरान और वेनेज़ुएला जैसे बड़े तेल नरियातक अमेरिकी प्रतिबंधों से सीमित हैं।
 - ब्राज़ील और गुयाना जैसे गैर-OPEC+ उत्पादक भी उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जिससे वैश्विक अतआपूर्ति बढ़ रही है।
 - अमेरिका में शेल उत्पादक में वृद्धि हुई है, जिससे बाज़ार अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है और OPEC+ नरियंत्रणों के प्रतिक्रम संवेदनशील हो गया है।
- मूल्य समर्थन से बाज़ार हसिसेदारी की ओर बदलाव: मूल्य स्थरीकरण के परयास वफिल होने के बाद, सऊदी अरब ने मूल्य के बजाय बाज़ार हसिसेदारी पर ध्यान केंद्रति करने की अपनी पुरानी रणनीतिको पुनर्र्जीवति कया।
 - सऊदी अरब को अपनी वशाल अतरिकित तेल उत्पादन कषमता तथा स्थरि राजस्व बनाए रखने के लयि स्थरि, मध्यम उच्च कीमतों को प्राथमकता देने के कारण "सवगि प्रोड्यूसर" के रूप में जाना जाता है।
 - हालाँकि जब अन्य उत्पादक अपने नरिधारति कोटे से अधिक उत्पादन करते हैं, तो सऊदी अरब उच्च लागत वाले उत्पादकों पर दबाव बनाने और अपने नेतृत्व को पुनः स्थापति करने के लयि बाज़ार में वृद्धि कर देता है (जैसा कविर्ष 1985-86, वर्ष 1998, वर्ष 2014-16 और

Total oil production from OPEC+ (OPEC and non-OPEC participants)

2022 production in million barrels per day



Data source: U.S. Energy Information Administration, *Short-Term Energy Outlook*, April 2023

Note: OPEC oil totals are crude oil; OPEC+ oil totals are crude oil and lease condensate.

वैश्विक तेल मांग किस प्रकार विकसित हो रही है?

- वैश्विक तेल मांग में गिरावट: [अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी \(IEA\)](#) के अनुसार, वर्ष 2025 में वैश्विक तेल की मांग में केवल 0.73% की वृद्धि होने की संभावना है।
 - 'अधिकतम मांग' (Peak Demand) सिद्धांत (यह विचार कि वैश्विक तेल मांग अपने उच्चतम बिंदु पर पहुँच जाएगी और फिर स्थायी रूप से कम हो जाएगी) को वैश्विक आर्थिक मंदी, बढ़ते EV अंगीकरण और सुदृढ़ जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई जैसे संकेतकों के साथ मान्यता प्राप्त हो रही है।
 - इन प्रवृत्तियों के साथ-साथ अमेरिकी टैरिफ युद्ध जैसे व्यवधानों के कारण वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (S&P ग्लोबल ने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2025 में केवल 2.2% और वर्ष 2026 में 2.4% रहने का अनुमान लगाया है, जो वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी के बाद सबसे कम दर मानी जा रही है) और व्यापार पूर्वानुमान में कमी आई है।
 - परिणामस्वरूप, तेल की मांग स्थिर हो सकती है तथा आपूर्ति संबंधी बाधाएँ कम होने पर भी कीमतें नहीं बढ़ सकती हैं।
- व्यापार जोखिम: [वैश्विक व्यापार संगठन \(WTO\)](#) ने वर्ष 2025 में वैश्विक व्यापार में 0.2% वार्षिक गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है। इसके कारण आपूर्ति में कटौती के बावजूद तेल की कीमतें कम रह सकती हैं, जिससे पारंपरिक आपूर्ति-मांग मूल्य तंत्र को चुनौती मिल सकती है।
- प्रतिबंध और आपूर्ति पिकेप की बाधाएँ: रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे प्रमुख तेल उत्पादक अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन (प्रतिबंध हटने पर स्थिति बदल सकती है) हैं, जिससे उनकी निर्यात क्षमता कम हो रही है।

वैश्विक तेल मूल्य अस्थिरता का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- भारत की बढ़ती तेल मांग: भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक (चीन और अमेरिका के बाद) है, जिसकी मांग वृद्धि (वर्ष 2024-25 में ~ 3.2%) वैश्विक दर से लगभग चार गुना है।
 - उम्मीद है कि भारत वर्ष 2025 में वैश्विक कच्चे तेल की मांग में लगभग 25% का योगदान देगा और वर्ष 2040 तक प्राथमिक मांग चालक बन जाएगा।
- अल्पकालिक लाभ: कच्चे तेल की कम कीमतें भारत के आयात बिल को कम कर सकती हैं, क्योंकि तेल की कीमतों में प्रत्येक 1 अमेरिकी डॉलर की गिरावट से सालाना लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होगी।
- दीर्घकालिक जोखिम: तेल राजस्व में गिरावट से खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की अर्थव्यवस्थाएँ कमज़ोर हो सकती हैं, जिससे द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और पर्यटन प्रभावित हो सकते हैं।
 - इससे खाड़ी में नौ मलियन से अधिक भारतीय प्रवासियों की नौकरी जा सकती है, जिससे विप्रेषण प्रवाह (लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर) खतरे में पड़ सकता है, जो भारत के [भुगतान संतुलन](#) को सहारा देता है।
 - तेल और गैस क्षेत्र से जुड़े कर राजस्व में भी कमी आती है, जिससे सरकारी वित्त प्रभावित हो सकता है।
- विविधीकरण की आवश्यकता: भारत के सामने हाइड्रोजन पर निर्भरता कम करने तथा अस्थिर तेल बाजारों से होने वाले जोखिमों को कम करने के लिये नए विकास चालकों को विकसित करने की रणनीतिक अनिवार्यता है।

प्रश्न: OPEC+ ने अपना ध्यान मूल्य नियंत्रण से हटाकर बाज़ार हस्तिसेदारी पर केंद्रित कर लिया है। इस परिवर्तन का वैश्विक तेल बाज़ारों और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रलिस

प्रश्न. वेनेज़ुएला के अलावा दक्षिण अमेरिका से नमिनलखिति में से कौन OPEC का सदस्य है? (2009)

- (a) अर्जेंटीना
- (b) ब्राज़ील
- (c) इक्वाडोर
- (d) बोलीविया

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न. "वहनीय (ऐफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टेनबल) विकास लक्ष्यों (एस० डी० जी०) को प्राप्त करने के लिये अनविर्य है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टपिणी कीजिये। (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/shift-in-opec-production-strategy>

